नंद किशोर ओझा

बनाम

अंजनी कुमार सिंह

(2007 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 297)

9 दिसंबर, 2009

[अल्तमस कबीर, एचएल दत्तू, न्यायाधिपतिगण.]

न्यायालय की अवमाननाः

न्यायालय को दिया गया वचन-उल्लंघन और अवज्ञा --बिहार राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती-उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में दिए गए निर्देश कि भर्ती के लिए सभी प्रशिक्षित शिक्षकों पर विचार करें-नहीं कार्यान्वित-उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. अदालत के आदेशों का पालन करने के वचन पर राज्य द्वारा वापस ले लिए गए।अदालत के आदेशों के रूप में अवमानना याचिका का पालन नहीं किया गया -अभिनिर्धारित-- न्यायालय के समक्ष प्रकट की गई सामग्री और कथित अवमाननाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुति दलीलों से संदेह के लिए बहुत कम जगह है कि भले ही राज्य के पास एक समय राज्य में तब उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति देने का इरादा था जब अंडरटेकिंग दिए गए थे, बाद में अपनी स्थिति बदल दी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने और

इसके अधिकारियों ने दिए गए उपक्रमों को लागू करने हेतु गलत सूचना की शरण ली है-- -जब अंडरटेकिंग दी गयी तो उसे को लागू किया जाना था- जब शिक्षक के खाली पदों पर प्रशिक्षित लोगों को समायोजित करने के लिए उत्तरवर्ती अंडरटेकिंग दी गयी, तो राज्य सरकार अपने पहले के अंडरटेकिंग से पीछे नहीं कर सकती हटें और ऐसे अंडरटेकिंग को प्रभावी नहीं करने के लिए नीति परिवर्तन का दावा नहीं कर सकती -इसके अलावा, योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों को दी गई नियुक्तियाँ उस समय जब वचन दिए गए थे, वे शिक्षा मित्रों के रूप में थे, जो नियुक्तियां कथित रूप से तदर्थ प्रकृति की थीं और उक्त अंडरटेकिंग के संदर्भ में विचार नहीं किया गया था - सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी ओर से दिए गए वचनों का पालन करने में विफलता के कारण उत्पन्न हुई समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए-- प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन दिसंबर, 2003 में प्रकाशित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, वह रिक्तियों की कुल संख्या निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए हमारे ध्यान में लाया गया था, जिसे 34,540 के रूप में दिखाया गया, जबकि अभी तक समायोजित किए जाने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुमानित संख्या उपरोक्त आंकड़े से कहीं अधिक थी--पूरे मुद्दे को शांत करने के लिए, हमने प्रशिक्षित शिक्षकों के दावों को पूरा करने के लिए विज्ञापन में दिखाए गए पदों पर रिक्तियों से संबंधित आंकड़ों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, जो नियमित आधार पर

नियुक्ति के लिए प्रासंगिक समय पर उपलब्ध थे--तदनुसार, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उपलब्ध होने के बावजूद, हम निर्देश देते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन में दर्शाई गई 34,540 की उक्त उपलब्ध रिक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की उक्त संख्या से भरा जाए जो वचन 18 जनवरी, 2006 और 23 जनवरी, 2006 को दिए गए थे-- तदनुसार, अवमानना का नियम जारी किए बिना, हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर, 2003 में प्रकाशित विज्ञापन में उपलब्ध दिखाई गई 34,540 रिक्तियों को वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरा जाए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक बार के आधार पर किया जाना है और इसे आगे परिपाटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए-- राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने और याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के परिणाम के बारे में अगली तारीख पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए अवमानना याचिका को छह सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाए-- बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2003--सेवा विधि-- प्राथमिक पाठशालाओमें शिक्षको की भर्ती.

विजय कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। (1998) 9 एस. सी. सी. 227 संदर्भित।

एसएलपी (सी) NO.22882/2004

पटना उच्च न्यायालय के C.W.J.C. सं 13246-6661/2003 , 1533 , 1788 , 1789 , 1861, 5053/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 1.7.2004 से.

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

1. इस अवमानना याचिका की पृष्ठभूमि 18 जनवरी, 2006 को दिए गए एक वचन और उसके आधार पर 23 जनवरी, 2006 को इस न्यायालय द्वारा 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 22882-22888 में पारित आदेश के कथित उल्लंघन की है। इस तरह के वचन के उल्लंघन और उसके आधार पर पारित बाद के आदेश की अवज्ञा के परिणामस्वरूप 2006 की अवमानना याचिका संख्या 207 दायर की गई, जिसे 19 मार्च, 2007 के एक आदेश द्वारा इस पश्च्यातवर्ती वचन के आधार पर निपटाया गया कि प्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

2. इसलिए, इस स्तर पर, उन पृष्ठभूमि तथ्यों पर गौर करना आवश्यक होगा जिसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य की ओर से वचन और उपरोक्त आदेश दिए गए।

3. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए बिहार राज्य के खिलाफ कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं। जाहिर तौर पर, उक्त मुद्दों को इस न्यायालय ने राम विजय कुमार और

अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [(1998) 9 एससीसी 227] के मामले में 5 सितंबर, 1997 के अपने आदेश में हल कर दिया था। हालाँकि, उसमें दिए गए निर्देशों को बिहार राज्य द्वारा लागू नहीं किया जाना प्रतीत होता है। वास्तव में, यह विनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5765/94) के मामले में 26 सितंबर, 1996 के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद था जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए इस न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निर्देश दिया गया था।जैसा कि 1 जुलाई, 2004 को पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से स्पष्ट होगा, बिहार राज्य ने पूरे बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को लागू नहीं करने के कारणों को समझाने का एक व्यर्थ प्रयास किया। दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी-बिहार राज्य और उसके अधिकारियों को राम विजय कुमार (उक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा विनोद कुमार (उक्त) के मामले में भी की।

4. शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार राज्य द्वारा दिनांक 10 दिसंबर, 2003 को जारी किए गए उत्तरवर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया गया, साथ ही बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2003 को भी रद्द कर दिया

गया। एक सकारात्मक निर्देश दिया गया कि उपलब्ध सभी प्रशिक्षित शिक्षकों की गणना की जाएगी और प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, आयु में छूट पर भी, चयन द्वारा या अन्यथा भर्ती के लिए विचार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई रियायतें भी रद्द कर दी गईं और यह संकेत दिया गया कि राज्य सरकार परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर सकती है जिन्हें ऐसा अवसर आने, पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 दिसंबर, 2003 के विज्ञापन के अनुसार किए गए सभी आवेदन भी रद्द कर दिए गए।

5. पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों से यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय की मंशा राज्य में बच्चों के व्यापक हितों और निरक्षरता को खत्म करने के लिए एक सार्वजनिक योजना के कार्यान्वयन की थी। बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा की योजना को बिना किसी देरी के लागू करने की आवश्यकता थी और यदि इस प्रक्रिया में परिस्थितियों और तात्कालिकताओं की आवश्यकता होती, तो अप्रशिक्षित शिक्षकों का चयन किया जा सकता था, जिन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि शिक्षकों की पूरी ताकत तैयार हो जाती तब भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता। यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी शिक्षकों, चाहे प्रशिक्षित हों या अप्रशिक्षित, की भर्ती करते समय राज्य सरकार को बिहार

शिक्षा संहिता, विशेषकर उसके अध्याय 6 और 7 को ध्यान में रखना चाहिए।

6. जब विशेष अनुमति याचिकाएं निपटान के लिए लंबित थीं, तब बिहार राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश का पालन करने के राज्य सरकार के निर्णय के मद्देनजर विशेष अनुमति याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। उक्त आवेदन में, बिहार राज्य ने प्रस्तुत किया कि सुशासन के अपने एजेंडे में, सरकार ने राज्य में शिक्षा के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। जहां तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, यह शिक्षकों के रिक्त पदों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर भर्ती करने और भरने तथा शिक्षकों की क्षमता और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए अन्य उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य का इरादा आवेदन के पैराग्राफ 5, 6 और 7 में विशेष रूप से दर्शाया गया था, जो इस प्रकार है:

> "5. इस बीच, यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जाए। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2003 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद, नए भर्ती नियमों पर विचार किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के

आदेश के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों को आयु में छूट देकर विकेंद्रीकृत तरीके से भर्ती की सुविधा प्रदान करना।

6. शिक्षकों की नियुक्ति करते समय **य** पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्राच्य शिक्षा एवं छात्रावास एवं मेस से संबंधित बिहार शिक्षा संहिता के अध्याय 6 एवं 7 को ध्यान में रखा जायेगा.

7. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों से कम होने की उम्मीद है, इसलिए उस सीमा तक चयन के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस बिहार लोक सेवा आयोग का संदर्भ लें प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती आवश्यक नहीं हो सकती है, और इस संबंध में माननीय न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया जा सकता है।"

7. विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने के लिए उक्त आवेदन का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 23 जनवरी, 2006 को उसमें किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर किया गया था।

8. चूँकि, बिहार राज्य कथित तौर पर अपनी प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों का पालन करने में विफल रहा, याचिकाकर्ता नंद किशोर ओझा

ने 2006 की अवमानना याचिका संख्या 207 दायर की। एक बार फिर, बिहार राज्य ने, बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती के सवाल पर विभिन्न तथ्य और आंकड़े प्रदान किए। हलफनामे में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी है और केवल जहां प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, वहां अप्रशिक्षित शिक्षकों के मामलों पर संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा विचार किया गया था।हालाँकि, बिहार राज्य की ओर से एक नया वचन दिया गया था कि उसके पहले के रुख को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 1 जुलाई, 2007 के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने के लिए उसके आवेदन में दर्शाया गया है। ऐसे ताज़ा आश्वासन के आधार पर, अवमानना याचिका का निपटारा 19 मार्च, 2007 को निम्नलिखित आदेश द्वारा किया गया:

> "अब दिए गए स्पष्ट बयान के मद्देनजर कि नियुक्ति में प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और दिनांक 7.2.2007 के उपरोक्त हलफनामे के पैराग्राफ 19 से 22 में दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर, हम बिहार राज्य को वचन को लागू करने का निर्देश देते हैं। बिहार राज्य द्वारा पहले भी और अब भी वर्तमान शपथपत्र दिनांक 7.2.2007 द्वारा

अक्षरश: प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है।"

9. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान अवमानना याचिका19 मार्च, 2007 के उक्त आदेश और 18 जनवरी, 2006 को दिए गए पहले के वचन और 23 जनवरी, 2006 के आदेश से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि वेतनमान वाले रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध किसी भी प्रशिक्षित शिक्षक को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, जो सरकार द्वारा 18 जनवरी, 2006 के अपने हलफनामे में दिए गए आश्वासन का घोर उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया गया कि तथ्य यह है कि निर्देश इस न्यायालय के 19 मार्च, 2007 के आदेश में दिए गए आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में स्वीकार किया गया है जिसमें कहा गया था कि 70,000 प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अन्य 35,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रमेश पी. भट्ट द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे, जैसा कि परिलक्षित होता है, वे 18 मार्च, 2007 को दिए गए वचन के अनुरूप नहीं थे। 19 मार्च, 2007 को पारित इस न्यायालय के आदेश में, राज्य सरकार को अपनी एसएलपी वापस लेने की प्रार्थना की अनुमति दी गई।श्री भट्ट ने अपने कथन के समर्थन में कई

निर्णयों का हवाला दिया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर और लगातार न केवल पहले दिए गए अपने वचन का उल्लंघन किया है, बल्कि 7 फरवरी, 2007 के अपने हलफनामे में भी इसकी पुष्टि की है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व अवमानना आवेदन का निपटारा करते हुए 19 मार्च, 2007 को आदेश दिया गया।

10. इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि अवमानना कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए कई आवेदन उन उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए थे जो अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता के समान ही प्रभावित थे।उक्त सभी आवेदनों को 23 अप्रैल, 2009 को अनुमति दी गई थी, और हमने उनकी ओर से प्रतिनिधि क्षमता में श्री एल. नागेश्वर राव और श्री राकेश यू. उपाध्याय, विद्वान वकील को सुना है।

1. श्री नागेश्वर राव ने प्रस्तुत किया कि जो नियुक्तियाँ कथित तौर पर रिक्तियों को भरने के लिए की गई थीं, वे बिहार राज्य की ओर से दिए गए वचनों से हटकर तदर्थ आधार पर की गई थीं और उसके आधार पर यह प्रयास किया गया था कि यह दिखाया जाए कि वचनों का अनुपालन किया गया है।यह प्रस्तुत किया गया कि नए अपनाए गए नियमों की चुनौती पर भी विचार नहीं किया गया, क्योंकि अवमाननाकर्ताओं की ओर से यह कहा गया था कि वे उन प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे जो उपक्रमों के अंतर्गत आते हैं।इसके अलावा, श्री उपाध्याय ने प्रस्तुत किया

कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद की रिक्तियाँ शिक्षा मित्रों द्वारा भरी गई थीं, न कि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, जैसा कि 18 जनवरी, 2006 और 7 फरवरी, 2007 के दो हलफनामों में दिए गए वचनों में विचार किया गया था।

2. श्री उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से दिए गए उपरोक्त वचनों से बचने के लिए एक चाल के अलावा कुछ नहीं थी।

3. कथित अवमाननाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कैलाश वासदेव ने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य की ओर से दिए गए वचनों का पर्याप्त अनुपालन किया गया है, क्योंकि कुल रिक्तियों में से 60,000 से अधिक प्रशिक्षित शिक्षक हैं। जिन्होंने आवेदन किया था, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया।यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 70,000 से भी कम थी।

4. श्री वासदेव ने यह तर्क देकर बिहार राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराने का भी प्रयास किया कि वचन दिए जाने और एसएलपी वापस लेने के बाद, बिहार राज्य ने इसके बाद बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियम, 2006 तैयार किया था। इसे "2006 नियम" कहा जाता है, जो 1 जुलाई, 2006 को लागू हुआ और समय-समय पर संशोधित

किया गया।श्री वासदेव ने प्रस्तुत किया कि उक्त नियमों के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पूरी प्रणाली को बदल दिया गया है।यह आग्रह किया गया था कि सहायक शिक्षकों का पद, जो पहले जिला स्थापना समिति द्वारा जिला स्तर पर भरा जाता था, बंद कर दिया गया था और 2006 के संशोधित नियमों के तहत, प्राथमिक स्तर पर स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति अब पंचायती राज संस्थाएँ द्वारा की जा रही थी। श्री वासदेव के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षक स्थायी थे, निश्चित वेतनमान पर थे और 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने के हकदार थे।श्री वासदेव ने प्रस्तुत किया कि नीति में बदलाव के मद्देनजर 2006 के नियमों के निर्माण के बाद प्रारंभिक स्तर पर स्कूल शिक्षकों की सभी नियुक्तियाँ की गईं और भविष्य में समय-समय पर संशोधित 2006 के नियमों के अनुसार समय पर की जानी होंगी। हालाँकि, श्री वासदेव ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह बहुत संभव है कि प्रशिक्षित-शिक्षकों में से कुछ उम्मीदवार नियुक्त किए गए लोगों की तुलना में कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने के कारण या रोस्टर प्रणाली के तहत एक विशेष श्रेणी में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति पाने में असफल रहे हों।श्री वासदेव ने प्रस्तुत किया कि यह भी संभव है कि प्रशिक्षित शिक्षकों में से कुछ उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाण पत्र नहीं थे या उन्होंने कथित तौर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए गए नकली प्रमाण पत्र खरीदे थे।

15. श्री वासदेव ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा उन प्रशिक्षित-शिक्षकों की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो अभी भी बेरोजगार हैं ताकि उनके मामलों को सत्यापित किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य से याचिकाकर्ता की ओर से ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप, विवरण के अभाव में, बिहार राज्य के लिए इस संबंध में लगाए गए आरोपों का प्रभावी ढंग से जवाब देना संभव नहीं था।

16. श्री वासदेव ने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य का इरादा कभी भी साशय और/या जानबूझकर अपनी ओर से दिए गए वचनों से पीछे हटने का नहीं था।इसने जो किया वह केवल 73 वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था, जिसके द्वारा प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 243 बी से 243-जी के तहत जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

17. हमने मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए दिए गए वचनों से पीछे हटने के लिए बिहार राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, कि रिक्तियों की संख्या आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या से

कहीं अधिक थी। दो वचनों में से पहला 18 जनवरी, 2006 को दिया गया था, जबकि श्री वासदेव के आग्रह के अनुसार, नवंबर 2005 में, बिहार राज्य में सरकार बदलने के साथ, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नीति को बदल दिया गया था। 73 वें संविधान संशोधन के तहत, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया गया। उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने आदेश दिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति विकेंद्रीकृत की जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से की जानी चाहिए।

18. यह प्रकट हुआ कि 2006 में बिहार में नई सरकार के आगमन और बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियम, 2006 के निर्माण के साथ प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में बदलाव हुआ है, जो 1 जुलाई 2006 को लागू हुआ और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया है।हालाँकि, हम बिहार राज्य की ओर से किए गए बचाव में कोई औचित्य नहीं देखते हैं कि नीति में इस तरह के बदलाव के कारण प्रशिक्षित शिक्षक जो उस समय मौजूद थे जब अंडरटेकिंग दी गयी थी, उन्हें समायोजित नहीं किया जा सका। जब ऐसे वचन दिए गए थे, तो उन्हें क्रियान्वित किया जाना था। चयन प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों को समायोजित करने के लिए लगातार वचन देने के बाद, राज्य सरकार अपने पहले के अंडरटेकिंग से पीछे नहीं हट सकती है और ऐसे अंडरटेकिंग को प्रभावी न करने के लिए नीति में

बदलाव का दावा नहीं कर सकती है। इसके अलावा, जैसा कि श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रशिक्षित शिक्षकों को दी गई नियुक्तियाँ, जो उस समय पात्र थे जब वचन दिया गया था, शिक्षा मित्र के रूप में थीं, जो नियुक्तियाँ कथित तौर पर प्रकृति में तदर्थ थीं और उक्त के संदर्भ में विचार नहीं किया गया था।

19. श्री नागेश्वर राव और श्री उपाध्याय द्वारा की गई दलीलों के मद्देनजर, कि शिक्षा मित्रों के पद पर की गई नियुक्ति बिहार राज्य की ओर से दिए गए वचन और श्री वासदेव द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार नहीं थी। श्री वासदेव ने कहा किउन प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्तियों की पेशकश की गई थी, जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था, हमने अपने आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2008 द्वारा, कथित अवमाननाकर्ता को उन प्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण देने वाला एक चार्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी, जिन्हें नियुक्तियों की पेशकश की गई थी, लेकिन जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान बिहार राज्य और उसके अधिकारियों की ओर से भी ऐसा कोई चार्ट कभी दायर नहीं किया गया था, इसलिए, श्री कैलाश वासदेव द्वारा की गई दलीलें अपुष्ट रहीं।

20. उपरोक्त उल्लेखित एक सामान्य बयान देने के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया वह यह की ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक, जो अंडरटेकिंग देते

समय ट्रेंड थे उनमे से किनको नियुक्ति नहीं मिली इस बाबत कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। यह भी विवरण प्रदान नहीं किया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों में से कौन से शिक्षकों को सेवा की स्थायीता के बिना और केवल तदर्थ आधार पर शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किया गया था।लेकिन, साथ ही, बड़ी संख्या में आवेदकों की ओर से कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि उक्त आवेदक भी प्रशिक्षित शिक्षक थे, जो याचिकाकर्ता के समान स्थिति में थे, जिनकी नियुक्ति स्थायी नहीं की जाकर अस्थायी रूप से रु. 5,000/- प्रति माह के समेकित वेतन पर किया गया। वास्तव में, आवेदकों की ओर से की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमने हस्तक्षेप के लिए सभी आवेदनों को अनुमति दे दी थी क्योंकि आवेदक 18 जनवरी, 2006 और 7 फरवरी, 2007 को दिए गए अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते थे। दुर्भाग्य से, यह दावा करने के कि नियुक्तियाँ दिए गए वचनों के अनुसार की गई थीं, इसके अलावा आवेदनों में आवेदकों की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में कथित अवमाननाकर्ता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

21. इस न्यायालय के समक्ष प्रकट की गई सामग्री और कथित अवमाननाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती हैं कि भले ही बिहार राज्य ने एक समय में राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति देने का इरादा किया हो, जब वचन दिए गए थे, तो उसने बाद में उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी, जिसके परिणामस्वरूप

बिहार राज्य और उसके अधिकारियों ने दिए गए वचनों को लागू नहीं करने के लिए दुष्प्रचार की शरण ली है। अंततः, विद्वान अटॉर्नी जनरल 25 अगस्त, 2009 को हमारे सामने उपस्थित हुए और हमें आश्वासन दिया कि बिहार राज्य का इरादा अपनी ओर से दिए गए वचन से पीछे हटने का नहीं था, बल्कि वचन के बाद के वर्षों में स्थिति बदल गई है और स्थिति उस समय जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक जटिल हो गई थी। इसलिए, मामले को स्थगित कर दिया गया ताकि वह इस बात पर विचार कर सकें कि मामले को सर्वोत्तम तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। अंततः, हालाँकि, कोई सकारात्मक समाधान नहीं सुझाया जा सका जो अंडरटेकिंग को संतुष्ट कर सके और साथ ही, इसे लागू करने में न्यूनतम मात्रा में व्यवधान पैदा कर सके।

22. सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी ओर से दिए गए वचनों का पालन करने में विफलता के कारण उत्पन्न हुई समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन दिसंबर, 2003 में प्रकाशित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, वह रिक्तियों की कुल संख्या निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए हमारे ध्यान में लाया गया था, जिसे 34,540 के रूप में दिखाया गया, जबकि अभी तक समायोजित किए जाने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुमानित संख्या उपरोक्त आंकड़े से कहीं अधिक थी। पूरे मुद्दे को शांत करने के लिए, हमने प्रशिक्षित शिक्षकों के दावों को पूरा

करने के लिए विज्ञापन में दिखाए गए पदों पर रिक्तियों से संबंधित आंकड़ों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, जो नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए प्रासंगिक समय पर उपलब्ध थे। तदनुसार, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उपलब्ध होने के बावजूद, हम निर्देश देते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन में दर्शाई गई 34,540 की उक्त उपलब्ध रिक्तियों को प्रभावी बनाने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की उक्त संख्या से भरा जाए जो वचन 18 जनवरी, 2006 और 23 जनवरी, 2006 को दिए गए थे।

23. तदनुसार, अवमानना का नियम जारी किए बिना, हम निर्देश देते हैं कि दिसंबर, 2003 में प्रकाशित विज्ञापन में उपलब्ध दिखाई गई 34,540 रिक्तियों को वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरा जाए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक बार के आधार पर किया जाना है और इसे आगे परिपाटी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

24. राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने और याचिकाकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के परिणाम के बारे में अगली तारीख पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए अवमानना याचिका को छह सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाए।

अवमानना याचिका स्थगन की जाती है.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **B.S.Pandiya** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।